भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3009

11 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कवरेज मानदंड

3009. श्री नवीन जिंदल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के कवरेज मानदंड में संशोधन करने पर विचार कर रही है ताकि उन लोगों को भी शामिल किया जा सके जो पौष्टिक आहार का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं लेकिन वर्तमान में मौजूदा आय आधारित कट-ऑफ से बाहर हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत श्री अन्न और समुद्री भोजन जैसे पोषक तत्वों की अधिकता वाले विकल्पों को शामिल करने के लिए दी जाने वाली वस्तुओं में विविधता लाने की कोई योजना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) राष्ट्रीय खाद्य लक्ष्यीकरण ढांचे में खाद्य वहनीयता सूचकांकों (जैसे "थाली सूचकांक") को शामिल करने के लिए नीति आयोग जैसे निकायों के साथ किए गए समन्वय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश भर में प्रवासी कामगारों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की हकदारियों तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए "वन नेशन, वन राशन कार्ड" योजना की स्थिति क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): सार्वजनिक वितरण प्रणाली अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के प्रावधानों के अनुसार शासित होती है। यह अधिनियम सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है और इसका उद्देश्य 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 81.35 करोड़ लाभार्थी हैं। अधिनियम के अंतर्गत कवरेज काफी व्यापक है ताकि समाज के सभी कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को इसका लाभ मिल सके।

इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार, राज्य के लिए निर्धारित लाभार्थियों की अधिकतम सीमा के भीतर, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों की पहचान केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट सीमा तक, उक्त योजना पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार करेगी, और शेष परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्राथमिकता वाले परिवारों के रूप में, राज्य सरकार द्वारा स्वयं विकसित ऐसे दिशानिर्देशों के अनुसार कवर किया जाएगा।

...2/-

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने लक्षित 81.35 करोड़ व्यक्तियों की तुलना में केवल 79.40 करोड़ व्यक्तियों की पहचान की है। फिर भी, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत 1.95 करोड़ और लाभार्थियों की पहचान करने की गुंजाइश है।

इस अधिनियम के तहत, पात्र लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार निशुल्क खाद्यान्न वितरित किए जा रहे हैं। "खाद्यान्न" शब्द को चावल, गेहूं या मोटे अनाज या इनके किसी भी संयोजन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो। इसलिए, मिलेट्स (श्रीअन्न) पहले से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का हिस्सा है। फिलहाल, इस अधिनियम के तहत और अधिक वस्तुओं को शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पोषण के स्तर में सुधार लाने के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिलेट्स (श्रीअन्न) खरीदने और स्थानीय खपत प्राथमिकताओं के अनुसार तथा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार लाभार्थियों को वितरित करने के लिए एक परामर्शिका जारी की गई है।

(घ): राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी) को लोकप्रिय रूप से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) सुविधा के रूप में जाना जाता है। इस प्रौद्योगिकी संचालित सुधार के माध्यम से, पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों को देश में कहीं भी, अपनी पसंद की किसी भी उचित दर दुकान (एफपीएस) से अपने पात्र खाद्यान्न को लेने का अधिकार दिया गया है, जिसके लिए वे अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) डिवाइस पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्राप्त कर सकते हैं। घर पर मौजूद परिवार के सदस्य भी उसी राशन कार्ड पर अपने गृह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से पीएमजीकेएवाई खाद्यान्न का हिस्सा ले सकते हैं। वर्तमान में, ओएनओआरसी सुविधा देश भर के सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सक्षम है, जो लगभग 100% पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों (प्रवासी श्रमिकों सहित) को कवर करती है।

*****